Food Subsidy to F.C.I.

*514. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) how much food subsidy was payable to the Food Corporation in the last three years;

(b) what are the handling charges of the F.C.I.;

(c) whether Government propose to reduce the handling charges and avoid wastage of foodgrains; and

(d) if so, what steps Government propose for the same?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The subsidy payable to the Food Corporation of India on its Central operations including carrying cost of buffer stocks was as follows:—

	Rs. Crores
1974-75 . . .	272·48
1975-76 . . .	297·72
1976-77 (R.E.) .	448·71

(b) The handling charges of the Food Corporation of India for its distribution operations were as follows:—

	Rs. Per quintal
1974-75 . . .	14·57
1975-76 . . .	16·54
1976-77(R.E.) . . .	14·82

(c) and (d). The handling charges of the Corporation were examined by a high powered Committee headed by Secretary (Food) and the Corporation had taken several steps to reduce the administrative overheads and other costs. These charges are being constantly kept under review so as to effect economy and maximum efficiency.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Food Corporation of India is a most mismanaged institution, and there is a lot of corruption and inefficiency in it; and the wastage per year runs into crores of rupees. This is obvious from the fact that the total deficit in 1976-77 is about Rs. 448 crores. It is double that of last year. May I know from the hon. Minister what were the main recommendations of this so-called high-power committee; what steps are being taken on each of its main recommendations, and the result of the action taken?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: My hon. friend has not seen that in 1976-77, the capacity of holding the grains has also increased. That is why the subsidy has also shown a trend of increase.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Has it become double?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It is not because of handling charges, or anything like that. It is not because of corruption, as he is alleging. It is because of the larger stocks that we are holding today.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: He did not answer my question: what were the main recommendations of the so-called high-powered committee, and what steps have been taken by government on each of its recommendations; and what is the result?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The details of the recommendations are not with me. I can supply them to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wants notice.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: It is really strange. This is a very relevant question regarding the high-power committee which was formed, and the recommendations made by it. He does not know what recommendations were made by that committee and what action has been taken on them. The Minister should be prepared, because he himself has replied that a high-power committee was set up; there are some recommendations and some action was taken. I want to know what are the recommendations and what action was taken on them.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The action taken is evident from the reply given by me. Replying to (b), I had stated that in 1975-76, the total charge was Rs. 16.54 per quintal, and that in 1976-77, it came to Rs. 14.82, i.e. about Rs. 2 less. This is because of that.

श्री कंवर लाल गुप्त : हैंडलिंग चार्ज के बारे में मेरा कहना यह है कि चौदह या सोलह रुपये जो भी ये हैं वे बहुत ज्यादा हैं। एफ० सी० आई० कई बार ऐसा करती है कि पंजाब से गेहूं खरीदा और उसको जाकर मद्रास में स्टोर कर देती है और उसके बाद वहां से जरूरत के वक्त दिल्ली में देती है। इस तरह से कोई तालमेल नहीं। कहां गेहूं खरीदा जाए, चावल खरीदा जाए और किन डेफिसिट स्टेट्स को वह भेजा जाना चाहिये, इसका उसको पता ही नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस अनाज की मूवमेंट जब दुबारा होती है तो उसमें खर्चा भाड़ा डबल पड़ जाता है और उसके साथ-साथ वेस्टेज भी डबल हो जाता है। आपने कहा कि डबल सबसिडी हो गई है, क्यों आपने ज्यादा अनाज रखा था ! 450 करोड़ की जो सबसिडी है वह बहुत ज्यादा है। आप 105 रुपये में गेहूं खरीदते थे और 129 में आप राशन कार्ड होल्डर्ज को देते थे। इस तरह से 24 रुपये का फर्क होता है। अब आप प्राइवेट ट्रेड को देखें। वह केवल तीन चार रुपये के फर्क पर बेचती है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब इतना नुक्सान हुआ तब कितना अनाज आपके पास था, उसके पहले कितना था और पहले नुक्सान क्यों कम होता था और अब ज्यादा क्यों होता है ? क्या यह ठीक है या नहीं कि आपने कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया कि कहां से माल खरीदा गया है उसको किन-किन डेफिसिट स्टेट्स में भेजा जाए ताकि हैंडलिंग चार्जिज कम हों ? क्या इसके लिए कोई पार्लियामेंटरी कमेटी आप बिठलाएंगे क्योंकि अभी तक आपने जो कमेटी सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बिठाई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे दोस्त यह सोचते हैं कि नुक्सान हो रहा है। यह सबसीडी भी इसमें से दी जाती है। इसमें हैण्डलिंग चार्ज भी लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्जिज भी लगते हैं। इसे 125 रुपये में रिलीज किया जा रहा है। पहले अनाज बाहर से आता रहा है।

हिन्दुस्तान में सारे स्टेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स नहीं हैं। कुछ स्टेट्स प्रोड्यूसिंग हैं, कुछ कंज्यूमर स्टेट्स हैं। हिन्दुस्तान में जहां सरप्लस होता है, वहां से दूसरी स्टेट्स को भेजना पड़ता है। लेकिन इस्यू प्राइज वही रखी गयी है। पिछले साल की प्राइस से केवल पांच रुपये प्रोक्योरमैंट प्राइस बढ़ायी गयी है।

मैं फिर कहता हूं कि यह नुक्सान नहीं हो रहा है, यह सबसीडी दी जा रही है।

This is the subsidy I have mentioned regarding that. Regarding the handling charges, as my hon. friend has suggested, the grains are produced in one State and taken to another State. It is always like that. There are certain consuming States. Suppose something is required in the Bengal region. If we can get it from UP, we will send it from UP. If it is not available in UP, then we will send it from Haryana or Punjab, the nearest available place. The FCI will

send food to the deficit areas from the nearest point.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दुबारा दिलाता हूं । पहले आप 105 रुपये में खरीदते थे और 125 रुपये में देते थे । 15 रुपये आपका हेण्डलिंग चार्ज था और पांच रुपये और चार्ज था । हो सकता है यह ट्रांसपोर्ट का हो । यह जो बीस रुपये क्विंटल का फर्क है इसमें आप कहते हैं कि सब्सीडी भी देते हैं । सब्सीडी देने का मतलब हुआ कि आपका ज्यादा खर्चा आता है तभी तो आप सब्सीडी देते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका कितना कास्ट आता है और आपको कितना नुक्सान पड़ता है जिसकी वजह से आपको सब्सीडी देनी पड़ती है ? क्या आप पार्लियामैंट की कोई कमेटी बिठायेंगे जो यह देखे कि कितनी सब्सीडी देनी पड़ती है, कितना आपका नुक्सान होता है ? बीस रुपये ज्यादा देने पर भी आपको सब्सीडी देनी पड़ती है, इसके लिए कोई पार्लियामैंट की कमेटी आप बिठायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ये डिस्ट्रीब्यूशन हेण्डलिंग चार्जिज हैं । रास्ते में अनाज लाने ले जाने में खर्च होता है, स्टोरेज में खर्च होता है । जहां पर अनाज खरीदा जाता है वहां पर खर्चा करना पड़ता है । मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, अगर आप कहें तो मैं बता दूं ।

If the hon. Member wants it. I can mention it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You set up a Parliamentary Committee to go into it.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We are considering it at the highest level, at the ministerial level.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: May I know from the hon. Minister whether it is a fact that huge quantities of foodgrains in FCI godowns in Calcutta have been found unfit for human consumption and the stock has been declared rotten? Is it a fact that the so-called rotten stock, together with 300 tonnes of fresh foodgrains, have been removed by the handling agents without payment of any cost and, if so, what action the FCI or the Agriculture Minister has taken against the handling agents?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I received a complaint only three days back regarding some storage at Calcutta. I will send an officer to make enquiries on the spot. I hope that he will submit a report within a day or two to me. Then appropriate action will be taken in the matter.

श्री राम विलास पासवान : यह फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया का मामला है और इसमें एक करोड़ से अधिक का खाद्यान्न भरा हुआ है जिसकी कीमत अब अरब रुपये से ज्यादा है । इस पर 10 प्रतिशत के करीब मैनेजमैंट पर खर्च होता है और 10 प्रतिशत ब्याज लगता है । इसके साथ ही जैसा कि श्री गुप्ता ने कहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में दामों में बढ़ोतरी होती है । फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के माल के बारे में यह बात जग-जाहिर है कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है यहां पर गेहूं में कंकड़, पत्थर मिला दिये जाते हैं ।

क्या इन सारी चीजों को देखने के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी जिससे आने जाने में विशेष खर्च न हो, मैनेजमैंट के और ब्याज के खर्चे जो लगते हैं, उनसे बचा जा सके और जो यहां धांधली है, भ्रष्टाचार है कंकड़-पत्थर मिला दिये जाते हैं, उनकी जांच के लिये कोई कमेटी बनाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बहुत से सवाल इकट्ठे हो गये हैं । जहां तक इसका ताल्लुक है कि यह इतना बड़ा भंडार क्यों इकट्ठा किया जाता है, तो यह बात तो साफ हो चुकी है कि कई बार अन्न नहीं होता है, बाहर के देशों से लाना पड़ता है और उसको रखना पड़ता है । बाहर अन्न की कीमतें 100

तक चली जाती है । इसलिये अन्न का भंडार बहुत जरूरी है और लाजमी तौर पर रखना पड़ता है । इसलिये अन्न को प्रोक्योर कर के रखते हैं, जहां जरूरत होती है इस्तेमाल करते हैं और जहां कमी होती है वहां भेजना पड़ता है । जहां तक कंकड़-पत्थर मिलाने की बात है, उस बारे में हम कांस्टैंट वाच कर रहे हैं । मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां से भी शिकायत आये, उसकी जांच फौरन कर के जो भी हलहो निकाला जाये और ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाये ।

Decline in inward Remittances

S.N.Q. 20. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether as reported by the "Economic Times", New Delhi, dated 7th July, 1977 inward remittances of foreign exchange into the country are on the decline;

(b) whether it is apprehended that the gradual decrease in remittances through legal channles may be matched by an increase in remittances through the compensatory payments rackets; and

(c) if so, the facts thereof and action taken thereto?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) For the reasons stated below, it is considered that merely on the basis of figures of inward remittances for two months, namely, April and May, 1977, referred to in the news item appearing in the 'Economic Times' dated 7th July, 1977, it would not be correct to come to the conclusion that the remittances of foreign exchange into the country are on the decline:—

(i) The inward remittances for the months of April and May, 1975 were respectively Rs. 66.65 crores and Rs. 96.67 crores and of April and May, 1976 were respectively Rs. 109.73 crores and Rs. 115.33 crores. The corresponding figures for April and May, 1977 are Rs. 145.08 crores and Rs. 137.94 crores. This is clearly a substantial increase compared to the amount of such remittances for the corresponding months in the years 1975 and 1976.

(ii) The total amount of remittances from January to May, 1977 comes to Rs. 708.93 crores. The corresponding figures for the same period during 1975 and 1976 were respectively Rs. 376.39 crores and Rs. 579.87 crores.

(iii) Temporary fluctuations have been noticed in the amounts of inward remittances in the previous years also.

(b) and (c). In view of the facts mentioned at (a) above, there is no cause for any apprehension. However, the field formations of the Enforcement Directorate have been alerted to be vigilant against the revival of compensatory payments and appropriate action as required under law will be taken in every such case.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: From the statement of the Finance Minister, it is clear that in 1975, between the months of April and May, there was an increase of over 40 per cent in inward remittances. The figures for 1976 shows that there was an increase of about 5 per cent. But in 1977, if you take into consideration the remittances for the months of April and May, it is Rs. 145.08 crores and Rs. 137.94 crores respectively. That means, even if you compare with the month of April and May, there is a decline to the extent of 5 per cent. That is also something which we should try to understand.

It is also a fact that certain people are trying to increase their activities of covering compensatory payments